भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
7–8–9 सितम्बर 2006
देहरादून (उत्तरांचल)

महंगाई पर प्रस्ताव

एनडीए सरकार से यूपीए सरकार को मजबूत अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई, जिसमें विकास की दर ऊंची थी, मुद्रस्फीति नियंत्रण में थी, विदेशी मुद्रा का भंडार अपने ही रिकार्ड को पार कर चुका था और कुल मिलाकर अभाव की अर्थव्यवस्था बहुलता में बदल गई थी। मूलभूत संरचना के निर्माण पर ज्यादा बल था।

अनाज के भंडार भरे हुए थे। उससे खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई और सरकार के काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रमों से सामाजिक कल्याण भी आगे बढ़ा। मुद्रास्फीति केवल नियंत्रण में ही नहीं थी बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम कम थे।

आम आदमी के साथ रहने का नारा देकर यूपीए सत्ता में आई, लेकिन यह सिद्ध हुआ कि यूपीए सरकार ही आम आदमी के खिलाफ एक साजिश है। देश में जबर्दस्त खाद्यान्न का संकट पैदा हुआ है। देश की जरूरत पूरी करने के लिए आज खाद्यान्न का भी बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सरकार को ऐसे खाद्य सकंट की जरा भी भनक नहीं थी। दुनिया के बाजार से विधमान कीमतों से ज्यादा कीमत चुकाकर आज आयात हो रही है।

गेंहूँ, चावल, दाल, दूध, शक्कर, खाद्य तेल, सब्जियां, फल, पैट्रोल, डीज़ल, लोहा, सीमेंट, पानी, बिजली, कपड़ा, गैस के दाम आसमान छू रहे है। मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूल–भूत चीजें लोगों की पहुंच से बाहर हो गयी है। गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग के जीवनयापन पर गहरा असर हुआ। मध्यम वर्ग का बजट भी इन जरूरतों को पूरा करते–करते चरमरा गया। विशेष बात यह है कि जब ग्राहकों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तब किसान का कुछ लाभ नहीं हो रहा है। किसान तो अपनी ही हालत पर विवश है और आत्महत्या पर तुला है।

वित्त मंत्री ने पिछले तीन साल में करों का बोझ बढ़ाने वाले बजट दिये है। यूपीए अत्याधिक कर लगाने वाला राज है। करों में बढ़ोत्तरी भी कीमतें बढ़ने का और मुद्रास्फीति का एक कारण है। यूपीए आम आदमी की जेब ही काट रही है।

आर्थिक दूरदृष्टि के अभाव में यूपीए सरकार खाद्यान्न के संकट को टाल नहीं सकी, इससे भी कीमतें बढ़ी है तथा भंडारण, कालाबाजार एवं स्पेक्यूलेशन बढ़ा है। केवल गेंहूँ के उत्पादन में थोड़ी सी कमी आई। अन्य उत्पादन एवं फसलें अच्छी रही। गेंहँ का उत्पादन

केवल 4 लाख टन कम हुआ लेकिन पिछले साल की तुलना में लगभग 100 फीसदी दाम बढ़े है। वास्तव में दाल, चीनी का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन फिर भी उनके दाम भी बढ़े है।

सरकारी गोदाम लगभग खाली है। अगस्त में 80 लाख टन के बजाय केवल 20 लाख टन का अनाज गोदामों में है। सरकार कीमतों पर लगाम न लगा सकने की इस स्थिति को बखूबी से समझकर व्यापारियों ने जमाखोरी शुरू की है।

खाद्यान्न दाल एवं चीनी जैसी आवश्यक चीजों में फॉरवर्ड ट्रेडिंग के कारण भी कीमतों में उछाल आया है। जब किसान खुद बाजार में सहभागी होता है तो फॉरवर्ड ट्रेडिंग का उसे लाभ होता है। लेकिन यहां तो दलाल ही ग्राहक एवं उत्पादक के हितों की बली देकर कीमतें प्रभावी कर रहे है।

राशन प्रणाली के चरमराने से भी कीमते बढ़ी है। गरीब को उसके लिए आवंटित अनाज का कोटा कभी पूरी तरह से नहीं मिलता क्योंकि उसकी बड़े हिस्सों की कालाबाजारी होती है।

ऐसे अभाव के काल में भी कॅमोडिटी एक्सचेंज चलाने से कीमतों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। राजग के शासन में खाद्यान्न का भंडार भरपूर भरा पड़ा था और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। खाद्यान्न रखने को जगह नहीं थी। काम के बदले अनाज की योजना में राज्यों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा था। उस समय खाद्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समीति ने भी अत्यधिक भंडारण को निकालने के लिए कहा। इसलिए खाद्यान्न के यातायात और व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाये गए। इस स्थिति में वस्तुओं के विनिमय केन्द्रों में फॉरवर्ड ट्रेडिंग को इजाजत दी गई। भाजपा ने खाद्यान्न के वायदे बाजार को समाप्त करने की मांग की, लेकिन उच्चस्तरिय भ्रष्टाचार के कारण सरकार ने यह निर्णय नहीं किया।

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में यूपीए सरकार ने 2 साल में 7 बार बढ़ाई। दामों में 58 फीसदी का इजाफा हुआ। जब राजग ने मई 2004 में सत्ता छोड़ी तब नई दिल्ली में पेट्रोल का दाम प्रति लीटर रू. 30.25 था, जो आज रू. 47.49 हो गया। डीजल की कीमत उस वक्त केवल रू. 20.49 थी, वह आज रू. 32.45 तक बढ़ गई। रसोई गैस की कीमतें भी 50 रू. से बढ़ी। पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया की तुलना में भारत में सबसे अधिक है। सरकार इन वस्तुओं पर लगी कस्टम तथा एक्साइज डयूटी से 1 लाख करोड़ रूपए से भी अधिक रकम जमा करती है।

चुनाव के समय कांग्रेस ने नारा दिया था "कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ", लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। जब–जब कांग्रेस सत्ता में आती है, भ्रष्टाचार, नियंत्रण, कतारें, प्रतीक्षा सूची, अभाव तथा कालाबाजार वापस आता है। जब कांग्रेस सत्ता से बाहर जाती है तब यह सारे राक्षस गायब होते है।

कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए यूपीए सरकार ने जो नाटकीय कदम उठाए वह बहुत देरी से और बहुत कम मात्रा में उठाये है। सरकार ने स्थिति को बिगाड़ा है। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि कांग्रेस सरकार का महंगाई से गहरा रिश्ता है। कांग्रेस का इतिहास आर्थिक दुर्व्यवस्था और गलत आर्थिक नीतियों से घिरा हुआ है।

धरातल की वास्तविकता छुपाने के लिए और महंगाई कम दिखाने के लिए आंकड़ों का जुगाली करने में कांग्रेस माहिर है। अगर सचमुच कीमतें जैसा की सरकार का कहना है कि केवल 5 फीसदी से बढ़ रही है, तो देशभर में आम आदमी इतना आक्रोशित क्यों है ?

राजग के शासन में महंगाई की औसतन दर 3 फीसदी था। यूपीए के काल में कभी यह 8 फीसदी तक पहुंच गया और 5 फीसदी से कभी कम नहीं आया। लेकिन, थोक मूल्य सूचकांक वास्तविकता को प्रकट नहीं करता। जनवरी में जब थोक सूचकांक 5.24 फीसदी था तब बाजार में आवश्यक वस्तुओं के दाम दुगने हुए थे और दालों में 35 फीसदी का उछाल आया था। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कुल मिलाकर 25 से 30 फीसदी तक इजाफा हुआ है।

आम आदमी के हितों को ध्यान में रखकर भाजपा मांग करती है :

1. राशन प्रणाली में हर राज्य, जिला एवं गांव को भेजा गया अनाज की मात्रा को पारदर्शि तरीके से सार्वजनिक करना चाहिए और इस प्रणाली से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए।

2. खाद्यान्न के उत्पादन, खरीद और राज्यों को वितरण के बारे में एक नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाए।

3. पेट्रोलियम पदार्थों पर लगे करो का सरलीकरण करके पुनर्विचार हो ताकि आम आदमी को राहत मिले।

4. खाद्यान्न का बफर स्टॉक पूरी मात्रा में बने रहने के लिए उत्पादन और खरीद की योजना सरकार पहले ही बनाए।

5. आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र में फॉरवर्ड ट्रेडिंग तथा कृषि उत्पाद में सट्टे पर प्रतिबंध लगाये।

– – –